many districts, which have a number of Old Age Homes. So, we have taken a decision that there will be an even spread an those districts which do not have old-age homes will hereafter get those first. We will, for the time being, not give further old-age homes to those districts, which already have a number of them.

(Question Nos. 245-246—Hon. Members absent.)

* [The questioner(s) Shri Kalraj Mishra and Shri O.T. Lepcha were absent. For answer *vide* page 18 infra.]

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपस्करों का उत्पादन

*247. **श्रीमती शोभना भरतिया** :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश और विदेश में 'ग्रीन पावर' सुविधाओं की स्थापना में प्रयुक्त होने वाले उपस्करों के लिए भारत को विनिर्माण और अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपस्करों के उत्पादन के लिए समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिनका निर्माण पूर्णत: निजी सरकारी सहभागिता के अनुरूप होगा;

(ग) क्या पांच राज्यों ने इस बारे में पहले ही अपनी रूचि दर्शा दी है; और

(घ) इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कब तक के लिए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) यह मंत्रालय अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हेतु उपस्करों के उत्पादन के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकर्त्ताओं द्वारा समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के सभी प्रयासों को सुगम बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के प्रति वचनबध्द है।

(ग) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रूचि दिखाई है।

(घ) इरेडा की सक्रिय भागीदारी से इच्छुक राज्य सरकारों और निवेशकों के साथ विचार-विमर्श किए जा रहे है।

Production of equipments for renewable energy generation

† * 247. SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: † †
SHRIMATI SUPRIYA SULE:

Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government is planning dedicated SEZs for the production of equipments involved in the renewable energy generation sector; aiming at giving a fillip to renewable energy generation besides developing India as a manufacturing and research hub for equipments used in the setting up of green power facilities in the country and abroad;

† Original notice of the question was received in Hindi.
†† The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Shobhana Bhartiya.

(b) whether Government has decided to set up SEZs for the renewable energy sector, to be constructed purely on a private-public partnership model;

(c) whether five States have already shown interest in this regard; and

(d) by when a final decision in this regard is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NE WAND RENEWABLE ENERGY (SHRI VILAS MUTTEMWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) The Ministry stands committed to facilitate and promote all efforts to establish dedicated Special Economic Zones for production of equipment involved in the renewable energy generation sector by domestic as well as foreign investors.

(c) Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have evinced interest to facilitate setting up of SEZs for renewable energy sector.

(d) Discussions with the interested State Governments and Investors are ongoing, with active participation of IREDA.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister what is the division within the renewable energy portfolio between solar, wind, biomass, etc., and how do we compare this with the international norms. And, if there is a specific area between the three where India has a competitive advantage and, if so, what are we doing to focus more in the areas where we do have the competive advantage.

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, वह स्पेशल इकोनोमिक जोन specially for renewals के बारे में था, लेकिन उन्होंने मंत्रालय के कार्यक्रम के प्रति जो रुचि बताई है, मैं बताना चाहूंगा कि मंत्रालय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-फ्यूल, बायो-मास, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सारे क्षेत्र में संशोधन करने का काम, उसको बढ़ावा देने का काम, उसे प्रमोशन करने का काम करता है तथा इसमें अभी तक जो उपलब्धि हुई है, वह ग्यारह हजार मेगावाट की हुई है और वह विशेष कर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंटा से आया है । अभी हमने ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना का जो योजना लक्ष्य रखा है, उसमें चौदह हजार मेगावाट से ज्यादा इस तरह के अक्षय ऊर्जा, रेन्युअल एनर्जी की वृध्दि होने की संभावना हम देख रहे हैं ।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, I asked, whether we have a competitive edge in any area. Does India have a natural edge because of rich natural resources? The point has not been answered by the hon. Minister.

श्री विलास मुत्तेमवार :माननीय सभापति जी, देश में ऊर्जा की कमी है और उसे बढ़ावा देने के लिए जिस तरह हमारा ऊर्जा मंत्रालय काम कर रहा है, उसके साथ ही, उनके साथ-साथ यह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, जो भी एनर्जी जिस माध्यम से यहां उपलब्ध होगी, उससे देश में ही लाभ होगा और जो सवा सौ हमारे गांव है, उसमें ऊर्जा पहुंचाने का जो काम है, उसके लिए हमारी मदद होगी । इस प्रकार जो भी वृध्दि होगी, वह देश का लाभ ही होगी ।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, according to the Ministry, though the potential of renewable energy is based on surplus agro-residues, in practice, there are barriers in collection and transportation of such agro-residues to the generation site and the biomass power generation units prefer to use fuel wood for techno-economic reasons. So, I would like to ask the hon. Minister, in view of this, how is the Government considering to encourage potential of grid interactive renewable energy which is based on surplus agro residues.

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय सभापति जी , मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे सारे स्रोत है, जिसमें सौर ऊर्जा है, बायो-मास है और पवन ऊर्जा है । बायो-मास में भी उसे बढ़ावा देने के लिए और उससे ऊर्जा निर्माण करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं और जैसे कि उनको वित्तीय सहायता दी जाती है, और कई तरह की व्यवस्था है, जिससे बायो-मास द्वारा ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister that we all have a lot of problems regarding land acquisition. So, how different is this programme going to be and what amount of land required to set up an SEZ of renewable energy?

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय सभापति जी, जो प्रश्न माननीय सदस्या ने पूछा है, मंत्रालय ने यह एक प्रयास किया है क्योंकि जिस तरह के इस क्षेत्र में आज उपलब्धियां आ रही है और नए-नए लोग इसमें निवेश करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें मदद देने के लिए मंत्रालय ने यह प्रयास किया है, इस दिशा में हमें उपलब्धि भी मिली है, देश के पांच प्रगत राज्यों ने इसमें रूचि बताई है। हमने अभी यह तय नही किया है कि इस प्रकार का SEZ कहां लगाया जाए, और राज्यों से बात हो रही है। इसके साथ ही जो SPV हम बनाएंगे, यह उन पर निर्भर करेगा कि हम कहां एसईज़ेड बनाएंगे । उसी के अनुसार यह तय किया जाएगा क्योंकि आज देश में एसईज़ेड को लेकर जिस तरह का वातावरण Land acquisition के संबंध में है, जिस तरह से आंदोलन हो रहे है, उसको परे रखकर ऐसी अड़चन हमारे एसईज़ेड में न आए, इसके लिए मंत्रालय प्रयास कर रहे है।

डा0 (श्रीमती) नजमा ए0 हेपतुल्ला : धन्यवाद महोदय, मैं ऑनरेबल मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि ग्रामीण विभाग में आप गोबर गैस बनाने के प्लांट डालते हैं और उनका कहीं-कहीं फायदा भी हुआ है। दूसरे भी कई तरह के एनर्जी उत्पादन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी आदि है। आप भी महाराष्ट्र से आते है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि मुम्बई शहर में कुछ इलाकों में बहुत से गाय-भैंसों के तबेले है और उनका जो गोबर होता है, क्या उसके इस्तेमाल के लिए आपने कुछ सोचा है क्योंकि उसका डिस्पोज़ल एक समस्या हो जाता है। मुम्बई में आपने देखा होगा कि जब वहां पानी का सैलाब आया था तो उससे कितनी गंदगी फैल गयी थी। क्या आपके पास इस संबंध में कोई स्कीम है?

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजना मंत्रालय में चल रही है और पूरे देश में, जेसे डेयरी कार्यक्रम है, अगर वे लोग हमारे पास प्रस्ताव लाते है, राज्य सरकार और राज्य सरकार की नोडल एजेंसी उसको रिकमेंड करती है तो उन्हें वित्तीय सहायता देने का काम, उनका डीपीआर बनाने का काम तथा उन्हें हमारे EREDA द्वारा लोन देने का काम हमारा मंत्रालय करता है। मुम्बई के बारे में भी अगर इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं तो उन पर अवश्य विचार किया जाएगा।

डा0 (श्रीमती) नजमा ए0 हेपतुल्ला : मंत्री जी, प्रस्ताव आए, वह अलग बात होती है। आपकी तरफ से क्या इनीशिएटिव लिया जाता है, उसके संबंध में भी तो आप हाउस को कुछ बताइए कि आप इस संबंध में क्या कर रहे है ?

श्री विलास मुत्तेमवार : सर, मंत्रालय द्वारा ये सारी योजनाएं हैं और इनको व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है। जिन-जिनको मालूम है, राज्य की जो नोडल एजेंसीज़ है, उनकी तरफ से प्रस्ताव आते है और उन पर विचार होता है। हमारी वेबसाइट पर भी इसका प्रचार किया जाता है और लोग आगे आ भी रहे है। PROF. P.J. KURIEN: Sir, there are two types of energy-renewable and fossil energy. The future of fossil energy is very bleak because the non-renewable resources of energy, like, coal, petroleum, etc., are getting depleted day-by-day. However, we have a very large potential of wind energy, and tapping the wind energy is not very difficult. I would like to know what the total potential of wind energy is. To what extent the potential of wind energy has been tapped; and what is your future plan for tapping the remaining potential so that the entire wind energy is tapped?

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय सभापति जी, हमारे देश में पवन ऊर्जा की क्षमता 45,000 मेगावाट से ज्यादा है और हमने अब तक साढ़े सात हजार मेगावाट का दोहन किया है। अभी आने वाली पंचवर्षीय योजना में हमने आठ से नौ हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है ।हमारे लिए यह बड़े फख्र की बात है कि दुनिया में आज हम चौथे नम्बर पर हैं। पीछे से आकर हमने जो प्रगति पवन ऊर्जा में की है, इससे भी ज्यादा जेनरेशन आने वाले दिनों में हो सकता है। इस क्षेत्र की तरफ मंत्रालय का पूरा ध्यान है।

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, if we go by the answer, given by the hon. Minister, it is very clear that no progress has been made, as far as setting up of the first SEZ in the area of

renewable energy is concerned. I would like to know from the hon. Minister, can he set any deadline for setting up this first SEZ in the field of renewable energy? Secondly, the solar energy is in abundance in our country. Is there any plan to foster the growth of solar energy?

श्री विलास मुत्तेमवार : सभापति, महोदय, जैसा मैंने बताया कि राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव आ रहे है, उसमें एक SPV हम बनाएंगे । यह उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है । उसके बाद ही हम जगह मुकर्रर करेंगे । हमारे मंत्रालय का प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय लें और कोई जगह तय करके उस पर एसईजेड की कार्यवाही शुरू करें ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Land for Kendriya Vidyalayas

*243. SHRI SANTOSH BAGRODIA:

SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of Kendriya Vidyalayas that need to be allotted;

(b) steps taken to secure land for such KVs; and

(c) whether it is a fact that a Parliamentary Committee has expressed reservation over the efforts made by the Ministry in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) There are 160 sanctioned Kendriya Vidyalayas (KVs) for which land is needed to be allotted by the sponsoring agencies. The sponsoring agency-wise break-up is given in Statement *(See* below).

(b) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has written to the sponsoring agencies for allotment of land. The matter has also been regularly followed up with them at various levels.

(c) The Department related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development in its 183rd report on Major issues concerning Kendriya Vidyalayas, presented on 30.11.2006, had only noted the discouraging picture about some KVs not having been allotted land even after several years. The Committee had appreciated the action of KVS in reduction of norms for land requirement and had suggested vigorous follow-up with the concerned agencies.

Statement

Details of Kendriya Vidyalayas requiring land

Sl.No.	.Name of Sponsoring Agency	Number of KVs where land is to be allotted
1	2	3
1	State Government	118
.2.	Union Territory Administration (UT)	01
3.	Ministry of Defence	29
4.	Ministry of Home Affairs	09